श्री रुद्रनारायण पाणि: सर ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no. This is not fair. Paniji, I find you interfering again and again. I will have to name you, if you don't correct your ways. Please.

Question No. 205

* 205. [The questioner Shri Ram Jethmalani was absent]

एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया के बीच के सौदे को रद्द किया जाना

*205. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि. के बीच 2005 में हुए एस बैण्ड स्पेक्ट्रम सौदे को हाल ही में रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सौदे को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सौदे में हुई अनियमितताओं की जांच की है;

(घ) यदि हाँ, तो की गई जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सौदे की जांच न करवाने के क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हाँ। जुलाई 2003 में मेसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड एवं अमरीका के मैसर्स फोर्ज एड्वाइजर के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप, एन्ट्रिक्स ने दो भू स्थिर उपग्रहों पर एस-बैण्ड में अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता के कुछ भाग को पट्टे पर देने हेतु, 28 जनवरी, 2005 को मैसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार तय किया था। इस करार और जून, 2007 में देवास द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को मिलाकर, 12 वर्षों के लिए दो उपग्रहों पर एन्ट्रिक्स द्वारा देवास को अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता का 90% पट्टे पर देने का प्रावधान था। इस करार का उद्देश्य, देश में उपग्रह-आधारित अंकीय मल्टीमीडिया सेवा को समर्थ बनाना था।

पिछले कुछ वर्षों में स्पेक्ट्रम के आबंटन के संबंध में सरकारी नीतियों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं, जिसमें रक्षा, अर्ध सैनिक बल, रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ शामिल हैं और एस बैण्ड स्पेक्ट्रम के आंबटन की बढ़ती माँग को, ध्यान में रखते हुए और देश की सामरिक महत्व की आवश्यकताओं के संबंध में सरकार ने एन्ट्रिक्स-देवास करार को समाप्त करने का निदेश दिया है। तदनुसार, एन्ट्रिक्स ने 25.02.2011 को देवास को करार समाप्त करने की सूचना भेजी है।

(ग) और (घ) जी हाँ। इस करार के कार्यान्वयन पर शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग ने 8 दिसम्बर, 2009 को, अंतरिक्ष आयोग के भूतपूर्व सदस्य डॉ.बी.एन. सुरेश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को, अंतरिक्ष विभाग को एन्ट्रिक्स-देवास करार को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करने का निदेश देने से पूर्व अन्तरिक्ष आयोग द्वारा जुलाई 2010 में विचार किये गये एन्ट्रिक्स-देवास करार के कानूनी, वाणिज्यिक, प्रक्रियात्मक तथा तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करने तथा जांच करने का आदेश प्राप्त था।

तदनन्तर, फरवरी 10, 2011 को सरकार ने सुधारात्मक उपाय सुझाने और चूक, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एन्ट्रिक्स तथा मेसर्स् देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार के तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रक्रियात्मक तथा वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Cancellation of deal between Antrix and Devas multimedia

†*205. SHRI RAM JETHMALANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the deal struck between the commercial sector of Antrix of Indian Space Research Organisation (ISRO) and Devas Multimedia Pvt. Ltd. in 2005 for S-Band spectrum has recently been cancelled;

(b) if so, the reasons for cancelling this deal;

(c) whether Government has looked into the irregularities related with this deal;

(d) if so, the details of the inquiry conducted; and

(e) if not, the reasons for not looking into the deal?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir.

Consequent to a Memorandum of Understanding signed in July 2003 between M/s Antrix Corporation Limited and M/s Forge Advisors of USA and the subsequent discussions, Antrix had

†Original notice of the question was received in Hindi.

entered into an agreement with M/s. DEVAS Multimedia Private Limited on 28th January 2005, for leasing part of the space segment capacity in S-band on two geostationary satellites. This agreement together with the option exercised by DEVAS in June, 2007 provided for leasing of 90% of the space segment capacity by ANTRIX to DEVAS on two satellites for 12 years. The objective of the Agreement was to enable Satellite-based Digital Multimedia services in the country.

Taking note of the fact that Government policies with regard to allocation of spectrum have undergone a change in the last few years and the increased demand for national needs, including for the needs of defence, para-military forces, railways and other public utility services as well as for societal needs, and having regard to the needs of the country's strategic requirements, Government directed Antrix to annul the Antrix-Devas agreement. Accordingly, Antrix has sent the Agreement termination notice to Devas on 25.2.2011.

(c) and (d) Yes, Sir. On receipt of the complaints on the implementation of the Agreement received in November 2009, Department of Space set up a Committee on December 8, 2009 chaired by Dr. B.N. Suresh, a former Member for Space Commission. This Committee was mandated to review and examine the legal, commercial, procedural and technical aspects of the Antrix-Devas Agreement that was considered by the Space Commission in July 2010 before directing Department of Space to take up action to annul the Antrix-Devas Agreement.

Subsequently, on February 10, 2011, the Government has constituted a High Powered Review Committee to review the technical, commercial, procedural and financial aspects of the agreement between ANTRIX and M/s Devas Multimedia Pvt., Ltd, to suggest corrective measures and to fix responsibility for lapses, if any. The Committee will be submitting its report very shortly.

(e) Does not arise.

MR. CHAIRMAN: Please don't deprive the hon. Member of his chance to put a question. आप बैठ जाइए प्लीज ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, जवाब ही नहीं मिला है, तो फिर सवाल पूछने का मतलब क्या है? ...(**व्यवधान**)... सर, फिर सवाल पूछने का मतलब क्या होगा?

श्री सभापति: प्रकाश जी, प्लीज ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: नहीं सर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की responsibility अधिकारी कैसे fix करेंगे, कृपया यह मुझे बताएं, यह मेरा सवाल है।

MR. CHAIRMAN: You are anticipating a situation.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No, he was there in the Space Commission. प्रधानमंत्री जी बता दें कि नहीं थे। एम.ओ.एस. थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पी.एम.ओ. के तीनों अधिकारी थे, तो responsibility उनकी fix होती है?

MR. CHAIRMAN: This is not the time for discussion.

श्री प्रकाश जावडेकर: नहीं, यह discussion नहीं है, यह सवाल है।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए प्लीज ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया है।

MR. CHAIRMAN: Please allow the other Members to put their questions.

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये कोई जवाब तो दें! ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज...प्लीज... प्रो. राम गोपाल यादव बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, यह जो जवाब आया है, इसके "ए" और "बी" भाग में Antrix और Devas में समझौता रद्द करने का जो कारण दिया है, तो उसमें और "सी" एवं "डी" भाग में जो उत्तर दिया है, उसमें contradiction है, एक विरोधाभास है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि तमाम needs बढ़ गई हैं, इस वजह से इसको annual किया गया और दूसरी तरफ शिकायत जब हुई, तब आपने एक कमेटी बनाई और कमेटी की अभी रिपोर्ट भी नहीं आई और उससे पहले ही उसको रद्द कर दिया गया। तो यह जो आपका answer है, यह लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने वाला है और संदेह इसलिए उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके जो दो geostationary satellites हैं और ISRO की जो व्यावसायिक सेवा "Antrix" है...

इसके जरिए जो 90 परसेंट स्पेस आपने देवास को दिया है, इसकी रीच 2जी स्पेक्ट्रम से बहुत ज्यादा है, कई गुणा ज्यादा है। 2जी स्पेक्ट्रम का जो मामला था, उसमें इतनी लम्बी अमाउंट थी, जिसकी चर्चा मुझे नहीं करनी है, लेकिन प्रश्न यह है कि जब यह इतना महत्वपूर्ण मामला है - फोर्सेज को पता नहीं चला, डिफेंस मिनिस्टरी को पता नहीं चला, पैरा मिलिट्री फोर्सेज के यूज का मामला था - और केवल 49 या 69 करोड़ में इस कंपनी को दे दिया गया? मैं तो यह कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को सदन को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि बिना आपकी जानकारी में लाए यह सब कैसे हुआ?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I would like to tell the hon. Member very humbly that transponders are required by the Government, especially, Defence, Paramilitary forces and for societal purposes. This is one aspect. The hon. Member wanted to correlate both the two. When the complaint was received, the complaint was investigated. Thereafter, the decision was taken. You

cannot see both of them in a different perspective. We will have to look into the complaint part. That is one aspect.

Second aspect is, this is required by the Government. In the Agreement, there is a clause that according to the terms of the Agreement, if it is required by the Government, the Government can use it for the purposes, underling the Agreement. That provision has been taken into consideration. Now, when the Review Committee submits its Report, the responsibility will be fixed and action will be taken by the hon. Prime Minister.

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: कितने दिन के बाद ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज, आप बैठ जाइए।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: As has been mentioned in the reply, the satellite-based digital multi-media services will be utilised for defence, paramilitary forces, railways and other public utility services as well as for societal needs. Whether the Government have got any proposal to empower the fishermen and also tribal people to get the benefit of this rich information technology and also help the students who are living in the remote areas.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the societal needs need not be exactly what the hon. Member wants. It will reach the rural areas also and the rural population will also get the advantage. Any information which they require, they will be able to get it through this system. Sir, it is an advanced technology. And, Sir, farmers are getting information even now through the system which is available now.

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: यह बात उनके ध्यान में कब आयी? ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी के ध्यान में यह बात कब आयी? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती माया सिंह: सर, आपने हमें इस पर प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I had to ask a very important question.

* 206 [The questioner Shri Rajkumar Dhoot was absent]

Industrial slow down

*206. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is every likelihood of industrial slow down in the country due to persistent rise in prices;